नाम - डा. प्रदीप कुमार राय
एसोसियेट प्रोफेसर, रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम।
विषय - राजनीति-शास्त्र
कक्षा - बी. ए. (प्रतिष्ठा) पार्ट-03, सत्र-2019-20
पेपर - 08
दिनांक - 30.07.2020

टॉपिक — माण्टेग्यू की घोषणा, 20 अगस्त, 1917 (Montague's Declaration August 20, 1917).

1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हो जाने, कांग्रेस में एकता स्थापित होने और कांग्रेस में उग्रदल का प्रभुत्व स्थापित हो जाने, भारतीयों द्वारा संयुक्त रूप से होमरूल की मांग की जाने और अंतिम रूप में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिये विवश कर दिया कि उसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने की घोषणा की जाये। नये भारत मंत्री मि. माण्टेग्यू उदारवादी दृष्टिकोण के थे। अतः उन्होंने उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये 20 Aug. 1917 को घोषणा की कि:
"साम्राज्य की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतया सहमत है यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक साथ लिया जाये तथा स्वशासन के कार्य में लगी हुई संस्थाओं को उत्साहित किया जाये जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके।"

घोषणा में प्रमुख रूप से निम्न बातें कही गयी थीं—

(1.) ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है।
(2.) उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है।
(3.) उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार ही कर सकती है, जिसपर भारतीय जनता की समृद्धि तथा उन्नति का उत्तरदायित्व है।
(4.) ब्रिटिश सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय भारतीय व्यक्तियों द्वारा किये गये सहयोग और उनके द्वारा दिये गये उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर किया जायेगा।

त्रुटियां — इस घोषणा पत्र में निराशाजनक बात यह जोड़ दी गई कि उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप में ही हो सकेगी और प्रत्येक नवीन चरण की प्रकृति और समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जायेगा। साथ ही यह कहा भी कि अंतिम का विकास भारतीयों के सहयोग

और उनके द्वारा प्रदर्शित सहयोग की भावना परिलक्षित होता है, भारतीयों को असहयोग के विरुद्ध एक अस्पष्ट धमकी भी दे दी गई थी।

~~और~~ <u>निष्कर्ष</u> - इसके बावजूद इस घोषणा से भारतीय शासन के विकास के नवीन युग का प्रारंभ हुआ। श्रीराम शर्मा के अनुसार, 'घोषणा-पत्र भारत के संवैधानिक इतिहास में एक अध्याय समाप्त करता है और दूसरा अध्याय प्रारंभ करता है।" अनेक भारतीयों द्वारा इस घोषणा को 'भारतीय मैग्नाकार्टा' के नाम से पुकारा गया है। इसी योजना के आधार पर [illegible] भारतीय शासन अधिनियम' पारित हुआ।